25 हजार हेक्टेयर घटी उत्तराखंड में कृषि भूमि। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में 517628 हेक्टेयर कृषि व परती भूमि थी, जो वर्ष 2017-18 में घटकर 492643 हेक्टेयर पर आ गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 7 मार्च 2020

भोपाल से दिल्ली तक शह-मात का खेल, दांव पर मप्र सरकार

सियासत के रंग ▶ बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए दिग्गज भाजपा नेताओं ने किया छह घंटे मंथन

कैबिनेट बैठक में दिखा तनाव, मंत्रियों के सुझाव पर भी नहीं हुई चर्चा

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में पांच दिनों से चला आ रहा शह-मात का खेल शुक्रवार को भी जारी रहा। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म रही। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे पर अड़े रहने से सियासी संकट और भी गहरा गया है। इस सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगले दो दिनों के अपने सारे कार्यक्रम रद कर दिए हैं। संकट से निपटने के लिए कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रबंधन में जुटे हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है। उधर, शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार को लेकर तनाव दिखा। मंत्रियों के सुझाव पर चर्चा बाद में करने की बात कहकर मामला टाल दिया गया।

भाजपा की ओर से अपने विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने भी उसके घर में सेंध लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी रणनीति के तहत दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पुरुषोत्तम कुमार तंतुवाय लापता हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि बसपा विधायक रामबाई उन्हें लेकर मुख्यमंत्री निवास आई थीं। उधर, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि जब वे बेंगलुरु से वापस आने के लिए निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया।

उधर, सरकार पर छाए संकट से तिलमिलाई कांग्रेस सरकार ने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की सुरक्षा भी हटा दी। पूर्व मंत्री संजय पाठक, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, विश्वास सारंग सहित कई नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों की सेवाएं सरकार ने वापस ले लीं।

भाजपा दिल्ली से सियासी हालात को अपने अनुरूप बनाने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा ने छह घंटे तक रणनीति बनाई। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा लगभग 12 कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में लाना चाहती है ताकि उसके दोनों काम हो जाएं। पहला, मध्य प्रदेश में वह सत्ता में वापस आ जाए और दूसरा राज्यसभा में दोनों सीटों पर उसका कब्जा बरकरार रहे।

तीनों कांग्रेस विधायक नहीं लौटे : कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल सिंह, रघुराज सिंह कंषाना और हरदीप सिंह डंग चौथे दिन भी भोपाल नहीं लौटे।

मध्य प्रदेश की सियासी गर्मी के बीच शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भोपाल पहुंचे। प्रेट्र

कमलनाथ बोले-हमारे नेता बिकाऊ नहीं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित एक सामाजिक समारोह में कहा कि हमारे नेता सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। हमें अपनी राजनीति की ऐसी पहचान बनानी है कि हमें उस पर गर्व हो। ऐसी पहचान बनाएं कि हम छाती ठोंककर कह सकें कि हम मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो नेता हैं, वे बिकाऊ नहीं हैं।

डंग ने पत्र लिखा है, जो इस्तीफा नहीं है : दिग्विजय

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा नहीं दिया है। वह कांग्रेस के साथ ही हैं। उन्होंने केवल पत्र लिखा है।

इस्तीफा विधिसम्मत नहीं : गोविंद

कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने डंग का इस्तीफा विधिसम्मत नहीं है। यह तब तक मान्य नहीं है, जब तक वह विधानसभा अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर उचित ढंग से नहीं देते हैं।

मैं सरकार के साथ : प्रदीप

इस बीच खनिज मंत्री व निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी उन अटकलों को खारिज किया कि वह कमलनाथ सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह कमलनाथ के साथ हैं।

नाराज विधायकों के साथ तैनात किए एक-एक मंत्री

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को पूरे समय डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। अलसुबह से देरात तक मंत्रियों-विधायकों के साथ उनकी मुलाकातें चलती रहीं। बेंगलुरु में मुसीबत में घिरे चार दिन से लापता सुरेंद्र सिंह शेरा से मोबाइल पर उन्होंने चर्चा की और मदद का भरोसा दिलाया। वहीं, नाराज चल रहे गैर कांग्रेसी विधायकों के साथ अब एक-एक मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है। मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ को शुक्रवार सुबह रामबाई के साथ दमोह भेजा गया तो बेंगलुरु में सुरेंद्र सिंह की मदद के लिए पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को भेजा गया। सपा विधायक संजीव कुशवाह और राजेश शुक्ला की भी चिंता की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की राजनीतिक उठापटक को भाजपा का ऑपरेशन लोटस कहे जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन मनी बैक है। वहीं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर निर्दलीय विधायक निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। विधानसभा में बहुमत के आंकड़ों में उलझी कमलनाथ सरकार को सवा साल में समय-समय पर निर्दलीय विधायकों ने पार लगाया है।

मप्र कांग्रेस सरकार के संकट पर भाजपा का दिल्ली में चिंतन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नरेंद्र तोमर के घर शिवराज सिंह चौहान समेत कई विधायकों की बैठक

मध्य प्रदेश सरकार पर छाये संकट के बीच राज्य भाजपा भी जद्दोजहद से गुजर रही है। दोनों ओर से एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के तीन विधायक अभी भी सरकार के संपर्क से बाहर हैं, वहीं माना जा रहा है कि कम से कम दो भाजपा विधायकों का रुख बागी है। दोनों ओर से दावे भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव व कुछ अन्य नेताओं ने मप्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिल्ली स्थित घर पर पूरी स्थिति पर चर्चा की।

यूं तो शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन में सम्मिलित होने के लिए पूरे देश से भाजपा नेता दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं ने इसे मंथन का एक अवसर बना लिया। सूत्र बताते हैं कि इन नेताओं की लगभग दो घंटे तक बैठक चली। गुरुवार को भी कुछ नेताओं के बीच विमर्श हुआ था। बताया जा रहा है कि भाजपा हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हाल है उसमें यह कहना भी मुश्किल है कि स्थिति भाजपा के पक्ष में है। दो नेता बागी दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस नेताओं की ओर से अभी और छह-सात विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है।

बताया जाता है कि भाजपा के लिए अपना कुनबा संभालने की भी चुनौती है। साथ ही अवसर आने पर सरकार गठन के लिए एक राय से तैयार रहने और संख्या बल में सौ फीसद दुरुस्त रहने की भी चुनौती है। हालांकि औपचारिक रूप से भाजपा नेता इससे साफ मना कर रहे हैं कि वह सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह ऐसा अवसर है कि जब भाजपा के अंदर ही अलग-अलग नेता विपक्षी खेमे में अपना प्रभाव दिखाकर अपनी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ाना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व की ओर से इन नेताओं को किसी भी बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है, लेकिन यह जारी है।

महाराष्ट्र के बजट में किसानों की कर्जमुक्ति पर जोर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▶ ठाकरे सरकार के पहले बजट में इस मद में 22000 करोड़ आवंटित

▶ आय बढ़ाने के लिए पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये का कर लगाया

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के पहले बजट में किसानों की कर्जमुक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। शुक्रवार को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने कहा कि 2019-20 में किसानों की कर्जमुक्ति के लिए 15000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जबकि 2020-21 के लिए इस राशि में 7000 करोड़ और जोड़ते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2019 के लिए कुल 22000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों की कर्जमुक्ति के लिए प्रावधान करने के अलावा बजट में ऐसे किसानों को भी राहत देने की घोषणा की गई है, जो समय पर कर्ज चुकाते रहे हैं। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कृषि कर्ज लेने वाले जो किसान 30 जून, 2020 तक अपने कर्ज की किस्तें समय पर अदा करते रहे हैं, उन्हें अधिकतम 50,000 रुपए की राहत प्रदान की जाएगी। 2018-19 में जिन किसानों का फसल ऋण 50,000 रुपए से कम रहा है और वे पूरा कर्ज अदा कर चुके हैं, ऐसे किसानों को उनके पूरे कर्ज के बराबर राहत राशि प्रदान की जाएगी।

बजट में आपदाग्रस्त किसानों के लिए केंद्र सरकार की सहायता कम मिलने की ओर भी इशारा किया गया है। इस संबंध में कहा गया है कि जुलाई-अगस्त 2019 में आई बाढ़ व अक्टूबर-नवंबर 2019 में हुई असमय बरसात से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 14,496 करोड़ की सहायता मांगी थी। लेकिन केंद्र की तरफ से सिर्फ 956.13 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार अपने कोष से किसानों को समय पर राहत देने में पीछे नहीं रही।

महाराष्ट्र विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। प्रेट

विधानसभा में वित्तमंत्री अजीत पवार व विधान परिषद में वित्त राज्यमंत्री शंबूराजे देसाई ने वर्ष 2020-21 के लिए जो बजट पेश किया उसमें 9,511 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान जताया गया है। तीन दलों वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार अपने गठन के पहले से ही किसानों को राहत देने की बात करती आ रही है। यह कर्जमुक्ति योजना उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।

बजट में जहां 2500 करोड़ की कर राहत देने की घोषणा की गई है, वहीं पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर एक रुपए का अतिरिक्त कर लगाकर 1800 करोड़ रुपए वसूली की योजना भी पेश कर दी गई है। बजट में उद्योग क्षेत्र को राहत देने की मंशा दर्शाते हुए उद्योगों के लिए दी जानेवाली बिजली पर मौजूदा शुल्क को 97.5 फीसद कर दिया गया है।

इससे सरकारी कोष पर 700 करोड़ का बोझ पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ एवं नागपुर मनपा क्षेत्र में मुद्रांक शुल्क व अन्य कार्यों पर लगनेवाले कर को दो साल के लिए एक फीसद कम कर दिया गया है। इससे भी सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान है।

राबड़ी के साथ चूहा लेकर विधान परिषद पहुंच गए राजद एमएलसी सुबोध कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ बांध काटने, शराब गटकने और फाइल कुतरने का मान रहे दोषी

▶ चूहे को सजा देने की मांग पर सदन में मुस्कुराते नजर आए नीतीश

बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को सदन से लेकर बाहर तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 'शराबी चूहा' चर्चा का विषय बना रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले 'बांध काटने, शराब गटकने और फाइल कुतरने वाले चूहे' को सजा दिलाने की मांग विपक्षी सदस्यों ने सरकार से की। राजद के मुख्य सचेतक सुबोध कुमार पिंजरे में चूहा लेकर विधान परिषद पहुंच गए। उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पिंजरा लेकर परिषद पोर्टिको में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सृजन समेत विभिन्न घोटालों का नाम लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए।

विपक्षी सदस्य यहीं नहीं रुके। वे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही चूहे को सजा दिलाने की मांग करने पर अड़ गए। इस बीच सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने पर विपक्षी सदस्यों ने कार्रवाई की मांग और तेज कर दी। सुबोध की मांग सुनकर मुख्यमंत्री सदन में मुस्कुराते नजर आए। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजद के घोटाले पर चुटकी ली।

चूहा रांची जेल में है बंद : भाजपा के आदित्य नारायण पांडेय ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि चूहा रांची जेल में बंद है। इस बीच नोकझोंक बढ़ते देख नीतीश कुमार सदन से निकल गए। सुबोध की बार-बार मांग पर भाजपा के रजनीश कुमार ने सभापति से मांग की कि राजद सदस्य सुबोध चूहा को पकड़े हुए हैं, इसलिए इन पर मुकदमा किया जाए।

बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को राजद एमएलसी सुबोध कुमार चूहा लेकर पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थीं। जागरण

चूहे की चर्चा क्यों ?

दरअसल, शराबबंदी के बाद बिहार के थानों में जब्त शराब का हिसाब चल रहा था, तो कई थानेदारों ने रिपोर्ट दी कि जब्त शराब इसलिए गायब है क्योंकि चूहे शराब पी गए। यह थानों के भ्रष्टाचार का मामला था। इसी तरह नियोजित शिक्षकों की भर्ती में धांधली की जांच के दौरान भी जिलों से रिपोर्ट आई कि कई फाइलें चूहे कुतर गए हैं। बांध टूटने पर भी यह कहा गया था कि चूहों ने बांधों को नुकसान पहुंचाया इसलिए बांध पानी का दबाव नहीं झेल सका।

बंगाल में शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों से पूछी मूलदेश की जानकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▶ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अथवा किसी अन्य मूलदेश के आवेदक को करना होगा उल्लेख

▶ पुरुष से सीने की परिधि और महिला उम्मीदवारों से मांगी अंडाशय और गर्भाशय की जानकारी

बंगाल में सीएए-एनआरसी के घोर विरोध के बीच ममता सरकार की तरफ से जारी की गई एक अधिसूचना को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। यह अधिसूचना बंगाल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज-विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अपने मूल देश की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों के साथ ही मंत्री के से बात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने बात नहीं की। ऐसे में शिक्षा विभाग की ऐसी जानकारी मांगने के पीछे मंशा क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो सका।

उम्मीदवारों से कहा गया है कि अगर वे मूलरूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अथवा किसी अन्य देश से हैं तो नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त इसका उल्लेख करें। इतना ही नहीं, पुरुष उम्मीदवारों से नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त उनके सीने की परिधि और महिला उम्मीदवारों से अंडाशय एवं गर्भाशय (अगर वे सामान्य हैं तो) के कार्य का विवरण भी मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही रक्तचाप, लिवर, दिल एवं फेफड़े की स्थिति का भी ब्योरा देने को कहा गया है।

शिक्षक संगठनों ने इस पर भारी नाराजगी जताई है। जादवपुर यूनीवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव पार्थ प्रतिम राय ने कहा-'हमारी समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से यह क्यों पूछा जा रहा है कि वे मूलरूप से किस देश के निवासी हैं। यह अधिसूचना सीएए की अवधारणा को मजबूत करती है, जो देश के प्रामाणिक नागरिकों को फिर से अपनी नागरिकता साबित करने को कहता है। हम इस अधिसूचना को अविलंब वापस लेने की मांग करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि पुरुष व महिला उम्मीदवारों से जिस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, उसका उनकी शैक्षणिक योग्यता से क्या लेना-देना है? यह किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने जैसा और असंवेदनशील है। राय ने कहा कि अगर इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो उनका संगठन अन्य शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। वहीं, ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जेयू चैप्टर ने भी इस अधिसूचना को अपमानजनक बताते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है।

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी सक्रिय

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गए हैं। वह राज्य के भाजपा सांसदों के साथ बैठककर विमर्श कर रहे हैं।

गत बुधवार को उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर से पार्टी सांसद व बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठक की। उसी दिन जयंत राय (जलपाईगुड़ी) एवं ज्योतिर्मय सिंह महतो (पुरुलिया) से भी बातचीत की। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने लॉकेट चटर्जी (हुगली), सौमित्र खां (विष्णुपुर) एवं निशिथ प्रमाणिक (कूचबिहार) के साथ अलग-अलग बैठक की। आने वाले दिनों में वे बाकी सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे।

भाजपा सूत्रों से मिली मुताबिक यह बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। दरअसल, पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के रास्ते में पार्टी के सामने क्या-क्या चुनौतियां पेश आ सकती हैं। उन्होंने पार्टी सांसदों से बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात की विस्तार से जानकारी ली है। साथ ही बंगाल भाजपा की सांगठनिक स्थिति के बारे में भी जाना है।

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें अब अगले विधानसभा चुनाव पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने पिछले रविवार को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में रैली में बंगाल में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कोई 'राजपुत्र' नहीं बल्कि 'भूमिपुत्र' बनेगा।

राज्यसभा की पांचवीं सीट पर भी तृणमूल की नजर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▶ संख्या बल के लिहाज से चार पर तृणमूल की जीत तय, पर 5वीं सीट पर भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। पांच राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। इन पांच में से चार सीटों पर तृणमूल की जीत निश्चित है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए उसके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर पांचवीं सीट पर भी है। इसीलिए तृणमूल नेतृत्व पांचवीं सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसके लिए उन्हें छह-सात वोटों की जरूरत है। ऐसे में तृणमूल की ओर से आवश्यक वोट जुटाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है।

सूत्रों के अनुसार पार्टी को पांच नामांकन पत्र लेने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पांचवीं सीट पर क्या तृणमूल भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है? क्योंकि, पांचवीं सीट पर माकपा व कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और करीब-करीब नाम माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का फाइनल हो चुका है। ऐसे में तृणमूल भी उस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो मतदान होगा। नहीं तो पांचों सीटें निर्विरोध घोषित हो जाएंगी। अभी तक तृणमूल ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। हालांकि, दिनेश त्रिवेदी, मनीष गुप्ता और मौसम बेनजीर नूर का नाम चर्चा में है। वहीं चौथी सीट से प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बक्शी और पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी के नाम की भी चर्चा है।

संकट

सांसद आजम खां और उनकी पत्नी व बेटे के जेल जाने के बाद विवि पर संकट, जिला प्रशासन को जौहर ट्रस्ट की नहीं दी जानकारी, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट

जौहर यूनिवर्सिटी को कब्जे में ले सकती है उप्र सरकार

मुस्लेमीन, रामपुर

सपा सांसद आजम खां के जेल जाने के बाद उप्र की योगी सरकार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को कब्जे में ले सकती है। सांसद आजम खां और उनकी पत्नी व बेटे के जेल जाने के बाद यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल छा रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसको संचालित कर रहे ट्रस्ट की रिपोर्ट नहीं मिलने पर शासन को अपनी भेज दी है। आजम खां यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ ही कुलाधिपति भी हैं। बेटे अब्दुल्ला सीईओ और ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इसी तरह आजम की पत्नी तजीन फात्मा भी ट्रस्ट की सदस्य हैं। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम भी सदस्य हैं। ये सभी अब जेल में बंद हैं। विवि को संचालित करने वाले जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां और दूसरे सदस्य भी फर्जीवाड़े में फंस गए हैं। ट्रस्ट द्वारा प्रति वर्ष की रिपोर्ट नहीं भेजकर नियमों का उल्लंघन किया गया।

जौहर यूनिवर्सिटी। फाइल

हालांकि यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खान का कहना है कि यूनिवर्सिटी ठीक से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी में करीब तीन हजार छात्र-छात्राएं हैं और तीन सौ का स्टाफ है।

नहीं भेजी गई प्रगति रिपोर्ट : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि ट्रस्ट को हर साल 1 अप्रैल को जिलाधिकारी को अपनी प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत कराना होता है, लेकिन जौहर ट्रस्ट ने कभी जिलाधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इसकी जांच की जा रही है। डीएम ने बताया कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी चलती रहे। हमने सरकार को भी रिपोर्ट दी है कि इसे टेकओवर कर लिया जाए और उसके मौजूदा स्वरूप में चलने दिया जाए। यह यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है। पिछले साल ही प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता पाई जाती है तो वहां प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

एक के बाद एक अनियमितताएं मिलीं : सपा सरकार में जौहर विवि बनाकर तैयार हुई। सत्ता बदलने के बाद शिकायतें शुरू हो गईं। प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कराई तो एक के बाद एक तमाम अनियमितताएं सामने आती गईं। जांच में पाया कि अल्पसंख्यक गरीबों को मुफ्त में शिक्षा नहीं दी जा रही है। लाइब्रेरी से पुलिस ने मदरसा आलिया से चोरी किताबें बरामद कर पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 26 किसानों ने आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मुकदमे दर्ज कराए थे। इसलिए उनको भूमाफिया घोषित कर दिया। किसानों की जमीन लौटाईं गईं। कस्टोडियन की करीब ढाई सौ बीघे को वक्फ संपत्ति बताया। इसमें आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चकरोड की जमीन की अदला-बदली करने में भी अनियमितता मिलीं। प्रशासन ने पिछले माह चकरोडों पर बनी यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी को तोड़कर रास्ता खुलवा दिया। यूनिवर्सिटी में कोसी नदी क्षेत्र की 140 बीघा जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया। अनु सूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना परमिशन के खरीदने का मामला भी सामने आया। प्रशासन ने जमीन को कब्जे में ले लिया। यूनिवर्सिटी की इमारतों का लेबर सेस भी अदा नहीं किया गया। इस पर श्रम विभाग ने 1.37 करोड़ की आरसी जारी कर दी, तब दो आलीशान इमारतों को कुर्क किया गया।

राज्यपाल ने शाह को बंगाल के हालात से कराया अवगत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▶ धनखड़ ने कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा

▶ वह हाल ही में हिंसा मुक्त निकाय चुनाव का कर चुके हैं आह्वान

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के हालात से उन्हें अवगत कराया। राज्यपाल के रूप में पद संभालने के बाद धनखड़ की शाह से यह पहली मुलाकात थी।

गौरतलब है कि धनखड़ की शाह से मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब राज्य की ममता बनर्जी नीत सरकार के साथ तल्खी की खबरें आ रही हैं। धनखड़ ने संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

एक सप्ताह पहले ही शाह ने कोलकाता का दौरा किया था, जहां एक रैली में केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर आक्रोश व्यक्त किया था। धनखड़ राज्य में कानून व्यवस्था पर कई बार चिंता जता चुके हैं। पिछले साल जुलाई में राज्यपाल का पद संभालने के समय से ही धनखड़ और राज्य सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर रस्साकसी चली आ रही है। हाल ही में उन्होंने हिंसा मुक्त निकाय चुनाव का आह्वान किया था।

पार्थ ने कहा -राज्यपाल, प्रचारपाल हैं: राज्यपाल व गृहमंत्री की मुलाकात पर राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्यपाल, प्रचार पाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में चहुंओर विकास हो रहा है।